

RNI : CHHHIN 2022/86325

स्वतंत्र बोल

www.swatantrabol.com



**अवैध टोल प्लाजा कब बंद होगा?
राजधानी में जमीनों का खेल..**



सरल सुगम सशक्त



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

प्रशासनिक
सुधार और
नवाचार

प्रगति और समृद्धि का सपना हो रहा साकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

प्रशासनिक सुधार



- सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना
- ई-गवर्नेंस को बढ़ावा, ई-ऑफिस प्रणाली
- अटल डैशबोर्ड
- मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप
- सीएम हेल्पलाइन 1076

राजस्व एवं पंजीयन सुधार



- प्रदेश में 119 पंजीयन कार्यालय बन रहे स्मार्ट
- भूमि विवाद रोकने जियो-रेफरेंसिंग
- 10 क्रांतियों और सुगम एप से आसान हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया
- वनाधिकार पट्टा वितरण से मिला मालिकाना हक

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस



- जन विश्वास 2.0 लागू करने वाला पहला राज्य
- इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ पोर्टल के वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम से त्वरित स्वीकृति
- स्टार्टअप एवं नवाचार नीति 2025-30 लागू
- भारत सरकार द्वारा LEADS 2025 में लैंडलॉकड राज्यों में हाई परफॉर्मर की मान्यता

सेवाओं का डिजिटलीकरण



- 6,000+ पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र
- सेवा सेतु से 661 से अधिक सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
- अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सुगम प्रक्रिया

भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं पारदर्शिता



- जेम पोर्टल से सरकारी खरीदी
- भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और नकल के विरुद्ध कठोर कानून
- खनिज ट्रांजिट पास की प्रक्रिया हुई पारदर्शी
- लकड़ी व खनिज ब्लॉक की पारदर्शी ई-नीलामी

स्वतंत्र बोल

www.swatantrabol.com

वर्ष : 05 अंक : 04 सितंबर 2026

प्रेरणास्त्रोत
स्व. जीवन गिरि गोस्वामी



संपादक
राहुल गिरि गोस्वामी



कानूनी सलाहकार
आनंद मोहन तिवारी
दिनेश मिश्रा



प्रचार-प्रसार-विज्ञापन
शेखर सागर



ले-आउट/डिजाइन
द्वारिका प्रसाद साहू

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक
राहुल गिरि गोस्वामी द्वारा
डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने
टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001 से प्रकाशित
एवं गुप्ता ऑफसेट समता कॉलोनी रायपुर
(छ.ग.) पिन-492001 से मुद्रित।
संपादक - राहुल गिरि गोस्वामी

रजिस्टर्ड कार्यालय
डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने
टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
पिन-492001

Email : Bolswatantra@gmail.com

Phone : 9754374333

(समस्त न्यायालीन प्रकरणों के
निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र रायपुर होगा।)

अवैध टोल प्लाजा...!



03

झीरमघाटी कांड : 13 साल बाद फैसला, 10 दोषी.. 06



छत्तीसगढ़ के दीपक संभालेंगे बीजेपी.. 09

मौत का ब्लू वाटर.. 11

राजधानी में जमीनों का खेल, जिम्मेदारों को.. 14



जीपी सिंह को पुलिस अकादमी की कमान.. 16

दूध से जुड़ी भक्ति की कहानी.. 21

अदालत में पीड़ित और गवाहों को मिलेगा सम्मान.. 26



बेरोजगारों के साथ छलावा..

छत्तीसगढ़ सहित देश भर प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्तियों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। देश अधिकांश राज्यों के भर्ती एजेंसियों पर धीरे धीरे युवाओं और बेरोजगारों का गुस्सा फूट रहा है। झारखण्ड में जिस तरह भर्तियों में अनियमितता हुई, एक-एक कुर्सी के कीमत तय कर बेचे गये.. उसे लेकर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। शोरेन सरकार को जाँच करने मजबूर कर दिया। यही हाल बिहार पीएससी का है और राजस्थान का। छत्तीसगढ़ इनसे अछूता नहीं है, यहां भी बड़ा घोटाला हुआ.. साल 2019 से लेकर 2023 तक हुई सभी भर्तियां संदेह के दायरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय जाँच कर रही, राज्य लोक सेवा आयोग के तत्कालीन मुखिया समेत उनके सहयोगी और अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। कुछ जेल में हैं तो कुछ बेल में.. सरकार आखिर बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ क्यों करती है? वर्षों तक नौकरी की तैयारी करने के बाद कही जाकर सफलता मिलती है, ऐसे में रसूखदारों को बिना मेहनत लाभ पहुँचाना, मेहनतकश अभ्यर्थियों का हक मारना कितना सही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीजीपीएससी घोटाले को मुद्दा बनाया था, युवाओं ने साथ भी दिया... अब वही संस्था में करीब सप्ताह भर से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इससे सरकार की गंभीरता दिखता है, सरकार को बिना देर किये तत्काल अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए, और युवाओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी देना चाहिए।

– राहुल गोस्वामी

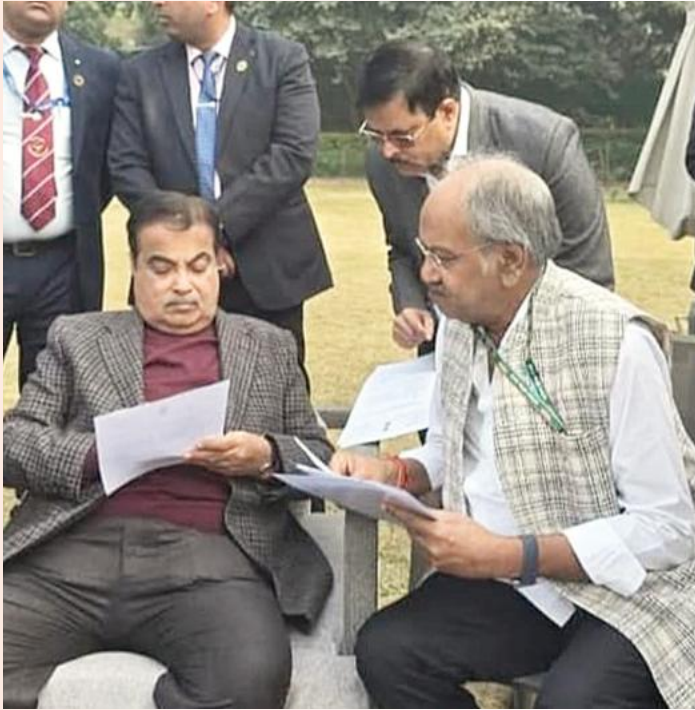
राजधानी के सीने पर

अवैध टोल प्लाजा...!

स्वतंत्र बोल डेस्क

रायपुर से दुर्ग भिलाई के रास्ते नागपुर जाने वाले लाखों लोगों को खारुन पार पर खड़ा अवैध कुम्हारी टोल प्लाजा मुँह चिढ़ा रहा है। जिस टोल प्लाजा को बंद करने बीजेपी सांसद ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर मुलाकात की, कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया वह आज भी धड़ल्ले से जारी है। साल 2006 में शुरू प्लाजा की मियाद 2015 में खत्म होना था पर आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। रायपुर से भिलाई के बीच सड़क निर्माण और उसकी लागत की वसूली के लिए टोल व्यवस्था शुरू की गई थी, शुरुआत में भिलाई के नेहरू नगर और कुम्हारी में अलग अलग टोल प्लाजा संचालित किए जाते थे। भिलाई के नेहरूनगर स्थित टोल प्लाजा बंद हुआ पर कुम्हारी का बंद नहीं हुआ। इसके बाद टोल की अवधि अलग अलग समय पर आगे बढ़ती रही। यही वजह है कि अब राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस टोल की अवधि वर्षों पहले खत्म होने की बात कही जा रही थी, वह आज भी क्यों जारी है?





गडकरी का आश्वासन निकला झूठा..!

कुम्हारि टोल को बंद करने की मांग का सबसे बड़ा आधार दुर्ग रायपुर आरंग बाईपास है। कोलकाता मुंबई मार्ग को जोड़ने वाले एनएच 53 पर लगभग 92 किलोमीटर लंबे दुर्ग रायपुर आरंग बाईपास को रायपुर और दुर्ग के बीच यातायात का वैकल्पिक मार्ग बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है।

राजनीतिक स्तर पर यह कहा गया था कि बाईपास के शुरू होने के बाद कुम्हारि टोल को बंद किया जाना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सामने भी प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने यह मुद्दा उठाया। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और दुर्ग के सांसद विजय बघेल सहित कई नेताओं ने टोल बंद करने की मांग की है, बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी से दिसंबर 2024 मिलकर इसे तत्काल बंद करने की मांग की थी जिस पर गडकरी ने 2026 में बंद करने

का आश्वासन दिया था। दुर्ग से बीजेपी के सांसद विजय बघेल ने टोल बंद करने की मांग किया था पर नतीजा सामने है। बीजेपी की सरकार में बीजेपी के सांसदों की सुनवाई नहीं हो रही है।

60 किलोमीटर के भीतर दूसरा टोल -

टोल प्लाजा के नियमों के अनुसार 60 किलोमीटर के भीतर दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। रायपुर और दुर्ग के आसपास धमधा नाका, मंदिर हसौद, ठेक, तरपोंगी और मरोद सहित दूसरे टोल प्लाजा की मौजूदगी में इस नियम अनदेखा किया जा रहा है। इसी नियम को आधार बनाकर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे बंद करने की मांग किया था। गडकरी द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार जून 2026 में बंद होना था, जो नहीं हुआ

उल्टा इसका टेंडर की समय सीमा बढ़ाकर अप्रैल 2027 कर दिया गया। टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ पर टोल की कीमते बढ़ गई है।

नितिन गडकरी
NITIN GADKARI

भारत सरकार
D.O. 22/12/24
MIN/RT&H/VIP/20-24



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

मंत्री
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
भारत सरकार
Minister
Road Transport and Highways
Government of India

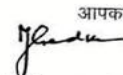
23 दिसंबर, 2024

प्रिय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी,

आपका पत्रांक: 2427, दिनांकित: 13.12.2024 प्राप्त हुआ, जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर 281 किमी. स्थित कुम्हारि टोल प्लाजा को बंद करने के संबंध में है।

उपर्युक्त पत्र को संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है।

सादर,

आपका

(नितिन गडकरी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल,
मा. संसद सदस्य (लोक सभा),
रामजी वाटिका, मौलश्री विहार,
वी.आई.पी रोड राम, मंदिर के पास,
रायपुर, छत्तीसगढ़-492001



सांसद बृजमोहन के चार प्रयास भी नाकाम?

- कुम्हारी टोल बंद कराने का मुद्दा रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल कई बार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सामने उठा चुके हैं।
- दिसंबर 2024 से इस मुद्दे को कई बार केंद्रीय मंत्री के सामने रखा गया। जून 2026 तक टोल बंद होने की उम्मीद भी जताई गई थी।
- लेकिन अब तक टोल बंद नहीं हुआ।

यही वजह है कि विपक्ष और स्थानीय राजनीतिक दल इसे सरकार के आश्वासन और जमीन पर वास्तविक स्थिति के बीच अंतर के रूप में उठा रहे हैं।

विजय बघेल भी उठा चुके हैं मुद्दा

दुर्ग सांसद विजय बघेल की ओर से भी टोल बंद कराने की मांग किए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाने और जनता को राहत दिलाने की मांग की थी। अब सवाल यह है कि जब सत्ता पक्ष के ही सांसद लगातार इस मुद्दे को केंद्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, तो समाधान क्यों नहीं निकल पाया?

विकास उपाध्याय का प्रदर्शन

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने टोल बंद कराने धरना प्रदर्शन, चक्काजाम भी किया था। उसके बाद भी अवैध टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ। विकास ने कहा सरकार लोगो को लूटने में लगी है, अवैध टोल प्लाजा को बंद करने के बजाय टोल का रेट बढ़ा दिया है।

1 अगस्त 2026 से बड़ी दरें होगी लागू-

- कार, जीप, वैन और एलएमवी का एकतरफा शुल्क 25 से बढ़कर 40 रुपये
- कार की वापसी यात्रा का शुल्क 40 से बढ़कर 50 रुपये
- हल्के वाणिज्यिक और मालवाहक वाहनों का शुल्क 40 से बढ़कर 65 रुपये
- तीन एक्सल वाहन का एकतरफा शुल्क 85 से बढ़कर 135 रुपये
- भारी निर्माण मशीनरी का शुल्क 165 से बढ़कर 185 रुपये
- सात या उससे अधिक एक्सल वाले वाहनों का शुल्क 180 से बढ़कर 275 रुपये
- मासिक पास की दरों में भी बढ़ोतरी

सवाल यह है कि जिस टोल को बंद करने की उम्मीद दिखाई गई थी, वह आखिर कब होगा या आम लोगो से लूट लगातार जारी रहेगा ?

13 साल बाद फैसला, 10 दोषी.. अनेक सवालों का जवाब नहीं..



स्वतंत्र बोल डेस्क

छत्तीसगढ़ इतिहास के सबसे भयावह राजनीतिक नरसंहारों में शामिल झीरम घाटी नरसंहार कांड में आखिर 13 सालों बाद निर्णय हो गया। जगदलपुर के NIA कोर्ट ने घटना में शामिल 10 नक्सलियों को दोषी ठहराया है, 13 वर्षों तक चले लंबी सुनवाई के बाद अंततः कोर्ट ने 05 सितंबर को आरोप तय किया, विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने दोषियों की सजा की अवधि पर सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है। 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से लौट रहे काफिले पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई थी। एनआईए के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार हमले में 27 लोग मारे गए और 38 घायल हुए, जिनमें 10 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। यह हमला इसलिए भी देश को झकझोर देने वाला था क्योंकि एक ही हमले में

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का लगभग पूरा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व खत्म हो गया था। हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र की भूमिका, राजनीतिक साजिश और हमले के पीछे मौजूद माओवादी नेतृत्व को लेकर वर्षों तक सवाल उठते रहे।

ऐसे हुआ झीरम का नरसंहार-

चुनावी साल में कांग्रेस ने प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाला था। यात्रा प्रदेश के अनेक हिस्सों से होते हुए 25 मई 2013

को सुकमा लौट रही थी, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। झीरम घाटी में रास्ता बाधित कर माओवादियों ने काफिले को रोक लिया। इसके बाद आईईडी और भारी गोलीबारी के जरिए हमला किया गया। एनआईए के रिकॉर्ड के मुताबिक हमला करीब शाम 4.15 बजे हुआ था। हमलावरों ने कांग्रेस नेताओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया। महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। यह सिर्फ एक नक्सली हमला नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए निर्णायक और बेहद त्रासदीपूर्ण घटना बन गया।

13 वर्षों में क्या हुआ..?

25 मई 2013 को शाम 4.15 बजे हमला हुआ, कई बड़े कांग्रेसी नेता और पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना ने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की सरकार ने राज्य सरकार ने घटना की परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित चूक की जांच के लिए 28 मई 2013 को



पर झीरम मामले में कथित बड़ी साजिश और आपराधिक षड्यंत्र को लेकर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। एनआईए ने इस जांच को अपने हाथ में लेने की मांग की, लेकिन मामला अदालतों तक पहुंच गया।

13 सालों की सुनवाई -

लंबी न्यायिक प्रक्रिया, सैकड़ों सुनवाईयों और गवाहियों के बाद 5 सितंबर 2026 को एनआईए की विशेष अदालत ने ट्रायल का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी

विशेष न्यायिक जांच आयोग गठित किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन हाईकोर्ट जज न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने की। राज्य की जांच एजेंसी के साथ केंद्र की जांच एजेंसी NIA ने जांच शुरू किया। NIA दर्जन भर आरोपितों को गिरफ्तार किया और 25 सितंबर 2014 को पहली चार्जशीट पेश किया।

28 सितंबर 2015 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जिसमें 30 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। कई आरोपी फरार रहे और उनके खिलाफ जांच जारी रखी गई।

सत्ता बदली, जांच पर सवाल -

2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने आरोप लगाया कि झीरम हमले के पीछे कथित बड़ी साजिश की पर्याप्त जांच नहीं हुई। जनवरी 2019 में राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय SIT गठित की, जिसे समयसीमा में रिपोर्ट देने निर्देशित किया गया। बीजेपी सरकार में गठित न्यायिक जांच आयोग की अवधि और दायरे को लेकर भी विवाद हुआ। आयोग ने नवंबर 2021 में रिपोर्ट पेश की, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने आयोग के दायरे में विस्तार किया। भाजपा नेता धरमलाल कौशिक ने इस कदम को हाईकोर्ट में चुनौती दी और 2022 में हाईकोर्ट ने संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा दी। इस घटना में कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार की शिकायत

ठहरा दिया। एक अन्य आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि चार्जशीट में नामजद कई अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए गए हैं। इस दौरान अनेक तरह की जांच और शिकायतें हुईं।

भूपेश की जेब से सबूत नहीं निकला..



NIA कोर्ट द्वारा 10 आरोपितों को दोषी ठहराने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'अधूरा न्याय' बताया। भूपेश के अनुसार केवल 10 निचले स्तर के आरोपियों को दोषी ठहराए जाने से झीरम की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, घटना के पीछे कथित राजनीतिक षड्यंत्र की जांच अब तक नहीं हुई। भूपेश ने सवाल उठाया कि जब एनआईए की जांच में बड़ी संख्या में माओवादियों के हमले में शामिल होने की बात सामने आई, तो सभी प्रमुख आरोपियों तक जांच क्यों नहीं पहुंची। झीरम का पूरा न्याय तभी होगा, जब हमले

के पीछे की कथित राजनीतिक साजिश और सुरक्षा से जुड़े सभी सवाल की भी जांच होगी। उन्होंने 2020 में दर्ज दूसरी एफआईआर और कथित साजिश की जांच आगे नहीं बढ़ने का भी मुद्दा उठाया। मीडिया में लगातार झीरम के साबुत जेब में होने का दावा करने वाले भूपेश बघेल अंत तक सबूत जाँच एजेंसी और कोर्ट को नहीं दे पाए।



सरकार ने फैसले को सही ठहराया-

प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने NIA कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अदालत द्वारा 10 आरोपियों को दोषी ठहराया जाना, इस बात का प्रमाण है कि एनआईए ने मामले में जो जांच की, उसके आधार पर अभियोजन अदालत में दोष साबित कर सका। कांग्रेसी राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय सबूत हैं तो उन्हें जांच एजेंसी देना चाहिए।

दोषी तो मिले, लेकिन मास्टरमाइंड कौन? - कांग्रेस

कांग्रेस ने फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन इसे पूर्ण न्याय मानने से इंकार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि झीरम हमला केवल माओवादी हिंसा नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र भी था, हालांकि इस आरोप की पुष्टि अदालत के मौजूदा फैसले से नहीं हुई है और राजनीतिक षड्यंत्र का पहलू अलग जांच का विषय है।

कोर्ट ने इन्हे दोषी पाया-

इस घटना में शामिल 10 नक्सालियों को कोर्ट ने दोषी पाया जिसमें प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना, सुमित्रा पुनेम मोडियम, मुक्का मांडवी, कोसा कवासी उर्फ कोसाराम, आयता मरकाम, मदकामी देवा, जोगा मदकामी, बनजामी सन्ना उर्फ चमरू/डेंगा और महादेव नाग शामिल हैं। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। 16 सितंबर को सभी दोषियों की सजा पर अदालत फैसला सुनाएगी। वही बचाव पक्ष ने फैसले के खिलाफ आगे अपील करने की बात कही है।

न्याय का एक पड़ाव, सवालों का अंत नहीं

झीरम घाटी का फैसला 13 साल से चले आ रहे आपराधिक मुकदमे में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अदालत ने ट्रायल का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी माना है। लेकिन इस मामले का राजनीतिक और सामाजिक असर इससे कहीं व्यापक है। एक तरफ पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि अब दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। दूसरी तरफ राजनीतिक साजिश, सुरक्षा चूक और हमले के व्यापक नेटवर्क से जुड़े सवालों को लेकर बहस जारी है, इसलिए 5 सितंबर 2026 का फैसला झीरम की न्यायिक यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय जरूर है, लेकिन 16 सितंबर की सजा और कथित बड़ी साजिश की जांच से जुड़े प्रश्न अभी भी इस मामले को चर्चा के केंद्र में रखेंगे।

एक नजर में

- घटना: 25 मई 2013
- स्थान: झीरम घाटी, बस्तर
- हमला: कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के काफिले पर माओवादी हमला
- NIA जांच: 27 मई 2013 से
- पहली चार्जशीट: 25 सितंबर 2014
- सप्लीमेंट्री चार्जशीट: 28 सितंबर 2015
- SIT: 2019
- दूसरी FIR: 25 मई 2020
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नवंबर 2023
- NIA कोर्ट का फैसला: 5 सितंबर 2026
- दोषी: 10
- सजा पर सुनवाई: 16 सितंबर 2026

नितिन नबीन की टीम

छत्तीसगढ़ के दीपक संभालेंगे बीजेपी का आईटी सेल और रूपकुमारी के जिम्मे महिला मोर्चा..

स्वतंत्र बोल डेस्क

नितिन नबीन की टीम में छत्तीसगढ़ को विशेष महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं, नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं ऐसे में वे यहाँ के बड़े छोटे सभी नेताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। उनकी टीम ने शामिल होने अनेक नामों को लेकर चर्चाये थे पर अप्रत्याशित रूप से रूपकुमारी चौधरी और दीपक मस्के को शामिल किया गया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्के को पार्टी का राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है। दोनों नियुक्तियों को छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए राष्ट्रीय संगठन में बढ़ती भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ रूपकुमारी चौधरी को देशभर में भाजपा के महिला



संगठन की कमान मिली है, वहीं दीपक महस्के के सामने पार्टी की डिजिटल और सोशल मीडिया रणनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।

रूपकुमारी चौधरी के हाथों महिला मोर्चे की कमान

महासमुंद की सांसद रूपकुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के साथ अब उनकी भूमिका प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठन को दिशा देने की होगी। रूपकुमारी चौधरी का राजनीतिक सफर संगठन और चुनावी राजनीति दोनों से जुड़ा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने वर्ष 2005 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया, साल 2013 में बसना विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनीं। इसके बाद भाजपा संगठन में प्रदेश मंत्री और अन्य जिम्मेदारियां भी संभालीं। लोकसभा चुनाव में महासमुंद से जीत के बाद उनका राजनीतिक दायरा और बढ़ा।





अब महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें देशभर की महिला कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक गतिविधियों के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी।

महिला संगठन के सामने कई चुनौतियां-

महिला मोर्चे की राष्ट्रीय जिम्मेदारी केवल संगठनात्मक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं होगी। महिला कार्यकर्ताओं को संगठन में सक्रिय भूमिका देने, नए नेतृत्व को तैयार करने और देश के अलग अलग हिस्सों में महिला संगठन को मजबूत करने की चुनौती भी उनके सामने होगी। पार्टी की महिला इकाई को बूथ स्तर तक मजबूत करना और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक एवं सामाजिक अभियानों से जोड़ना भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

दीपक के हाथो सोशल मीडिया की कमान-

दीपक महस्के ने वर्षों से बीजेपी का आईटी सेल का काम संभाल रहे अमित मालवीय की जगह लिया है। उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सोशल मीडिया/आईटी सेल का संयोजक बनाया गया है। पार्टी के सोशल मीडिया अभियानों, डिजिटल कम्युनिकेशन और ऑनलाइन संगठनात्मक गतिविधियों के समन्वय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। महस्के को पार्टी की आईटी और डिजिटल गतिविधियों से जुड़े अनुभव के कारण यह

जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने छत्तीसगढ़ भाजपा के आईटी संगठन में भी काम किया है और चुनावी अभियानों में सोशल मीडिया तथा डिजिटल नेटवर्क के इस्तेमाल से जुड़े दायित्व संभाले हैं। दीपक ने अमित मालवीय की जगह लिया है, वे मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं।

पार्टी का चेहरा चमकाना चुनौती-

राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं रह गया है। राजनीतिक संदेशों को तेजी से लोगों तक पहुंचाना, कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना और ऑनलाइन अभियान चलाना पार्टी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऐसे समय में राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दीपक महस्के के सामने देशभर में पार्टी के डिजिटल नेटवर्क के साथ समन्वय और सोशल मीडिया अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की चुनौती होगी।

भाजपा की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ से दो नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने को प्रदेश संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि दोनों नेताओं की जिम्मेदारियां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं। रूपकुमारी चौधरी महिला संगठन की राष्ट्रीय कमान संभालेंगी, जबकि दीपक महस्के डिजिटल और सोशल मीडिया की रणनीति में भूमिका निभाएंगे। यानी एक जिम्मेदारी सीधे संगठन के महिला नेटवर्क से जुड़ी है और दूसरी पार्टी के तेजी से बढ़ते डिजिटल विस्तार से। राष्ट्रीय संगठन में मिली इन जिम्मेदारियों ने छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए एक नया अवसर भी पैदा किया है। अब दोनों नेताओं के कामकाज और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका पर प्रदेश की राजनीतिक नजरें भी रहेंगी।

मौत का ब्लू वाटर

हर साल मर रहे लोग, चेतावनी बोर्ड के भरोसे सुरक्षा..

स्वतंत्र बोल डेस्क

रायपुर और नवा रायपुर के बीच में एयरपोर्ट के पास ब्लू वाटर खदान एक बार फिर चर्चा में है। ब्लू वाटर दूर से देखने पर बेहद आकर्षक दिखाई देता है। नीले रंग का पानी और आसपास का प्राकृतिक वातावरण लोगों को अपनी ओर खींचता है। यही आकर्षण इस जगह को युवाओं और आसपास के लोगों के लिए जोखिम भरा बना देता है। यह कोई अधिकृत पर्यटन स्थल नहीं है, इसके बावजूद लोग यहां पहुंचते हैं और पानी के करीब जाते हैं। हालिया हादसे में भी आदिल दोस्तों के साथ यहां पहुंचा था। पानी में उतरने के दौरान वह

गहरे हिस्से में चला गया और उसकी जान चली गई। इस बार 24 वर्षीय छात्र आदिल खान की डूबने से मौत हो गई, आदिल के डूबने के बाद रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे तक तलाश की, लेकिन गहरे और ठंडे पानी के कारण अभियान चुनौतीपूर्ण बना रहा। करीब 77 घंटे बाद आदिल का शव पानी की सतह पर मिला। इस बीच इंडियन नेवी की विशेष टीम को बुलाने की तैयारी तक करनी पड़ी। यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। असली सवाल यह है कि जिस जगह पर वर्षों से डूबने की घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे.. वहां अब तक स्थायी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बन सकी?



जिला प्रशासन फेल !



आदिल के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ उसकी मौत नहीं, बल्कि उसके शव को खोजने में लगा लंबा समय भी है। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने तलाश शुरू की, लेकिन पानी की गहराई और तापमान ने अभियान को बेहद कठिन बना दिया। रेस्क्यू टीम से जुड़े लोगों के अनुसार पानी 200 फीट से अधिक गहरा है और करीब 50 फीट नीचे जाने के बाद पानी बेहद ठंडा हो जाता है। ऐसे में स्कूबा डाइवर्स के लिए अधिक गहराई तक जाना चुनौतीपूर्ण हो गया। चार दिनों बाद भी आदिल का शव नहीं मिलने पर राज्य सरकार ने इंडियन नेवी की विशेष टीम को बुलाने की तैयारी की, हालांकि नेवी की टीम के पहुंचने से पहले ही करीब 77 घंटे

बाद आदिल का शव पानी की सतह पर आ गया था। इस पुरे घटनाक्रम में रायपुर जिला प्रशासन फेल रहा, जिला प्रशासन के अधिकारियों विशेष कर कलेक्टर गौरव सिंह ने मौके पर जाकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। मृतक के परिजन इसी बात को लेकर आक्रोशित थे, कि किसी रसूखदार के परिवार में ऐसी घटना होने पर भी जिला प्रशासन द्वारा इतनी ही लापरवाही की जाती ? इस घटना ने अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ दिया।

चेतावनी बोर्ड के भरोसे..

ब्लू वाटर में केवल चेतावनी बोर्ड होने और प्रभावी फेंसिंग या प्रवेश नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होने की बात सामने आई है। जिस जगह पर अब तक 10 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है, वहां लोगों की आवाजाही रोकने के लिए मजबूत भौतिक अवरोध क्यों नहीं बनाया गया, यह सवाल अब पहले से ज्यादा गंभीर है।

सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगा देना और यह मान लेना कि लोग खतरे को समझकर वापस चले जाएंगे, क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है? अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित या खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे रोकने के लिए





फेंसिंग, नियंत्रित प्रवेश, निगरानी और स्पष्ट चेतावनी व्यवस्था जरूरी है। खासकर ऐसी जगह पर जहां पानी की गहराई बेहद अधिक बताई जा रही है।

खदान बंद हुई तो गड्ढा क्यों नहीं भरा गया?

ब्लू वाटर प्राकृतिक झील नहीं है। यह पत्थर खदान था, यहाँ से पत्थरे खोदकर निकाली गई और खुला छोड़ दिया गया। जिस गड्ढे में आज पानी भरा हुआ है, वह कभी खनन के लिए खोदा गया था। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि खनन कब शुरू हुआ, कब बंद हुआ और खदान बंद होने के बाद इसके पुनर्वास और सुरक्षा के लिए क्या योजना बनाई गई थी। भारत में माइन क्लोजर की व्यवस्था के तहत प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान और फाइनल माइन क्लोजर प्लान का प्रावधान है। खदान बंद होने के बाद सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पुनर्वास से जुड़े उपाय स्वीकृत योजना के अनुसार किए जाने होते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर बंद खदान को मिट्टी से पूरी तरह भर देना ही एकमात्र कानूनी उपाय हो। खदान बंद होने के बाद भी सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ब्लू वाटर को लेकर अब यह जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि यहां खनन कब हुआ था, किस खनिज के

लिए हुआ था, किस एजेंसी या कंपनी के पास खनन की अनुमति थी और खनन कब बंद किया गया। यही ब्लू वाटर मामले की सबसे महत्वपूर्ण जांच का विषय होना चाहिए।

2017 से अब तक 10 मौतें

आकड़ों के मुताबिक ब्लू वाटर में वर्ष 2017 से अब तक 10 लोगों की डूबने से मौत हुई है। अक्टूबर 2025 में दो स्कूली छात्रों की मौत के बाद भी यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे, इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ और अगस्त 2026 में आदिल की मौत ने एक बार फिर प्रशासनिक इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना से गोताखोरों और आपदा प्रबंधन के तैयारियों की पोल खोल दी। छत्तीसगढ़ में गहरे जलाशयों, खदानों और तेज बहाव वाले जल क्षेत्रों में बचाव के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डीप डाइविंग विशेषज्ञ मौजूद हैं, अगर ऐसी विशेषज्ञ क्षमता सीमित है, तो गंभीर हादसों में दूसरे राज्यों या केंद्रीय एजेंसियों की टीम का इंतजार करना पड़ सकता है। जबकि डूबने की घटनाओं में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है।

कलेक्टर और एसडीएम का खेल

राजधानी में जमीनों का खेल, जिम्मेदारों को अभयदान!

स्वतंत्र बोल डेस्क

राजधानी में प्रत्येक आईएस अधिकारी कलेक्टर और राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार के रूप में पोस्टिंग जरूर चाहते हैं।

इसमें कामयाब वही होते हैं, जो सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करते हैं और सरकार के भरोसे में

हो। राजधानी में पोस्टिंग मिलते ही अधिकांश कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार जमीनों के काम में उलझ रहे, बीते

दस सालों के रिकॉर्ड

को देखे तो अधिकांश अधिकारियों ने इसी गलती को दोहराया। भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाला भी यही हुआ था। अब एक बार फिर जमीनों के खेल में जिम्मेदार उलझ रहे हैं। इस बार कलेक्टर गौरव कुमार सिंह और एसडीएम नंदकुमार की जोड़ी कमाल कर रही है।

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण रेल परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना से देशभर में माल ढुलाई के विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल

होगा। पश्चिम बंगाल के डकुनी से होते हुए उड़ीसा के रास्ते दुर्ग और रायपुर होते हुए सूरत गुजरात तक कॉरिडोर बनना प्रस्तावित है। जिसके चलते रेल मंत्रालय ने रायपुर, दुर्ग और संबंधित जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर रास्ते में आने वाले गाँवों की जमीनों के

डायवर्सन, बटांकन और खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि मुआवजा वितरण के नाम पर बंदरबांट और भ्रष्टाचार ना हो।

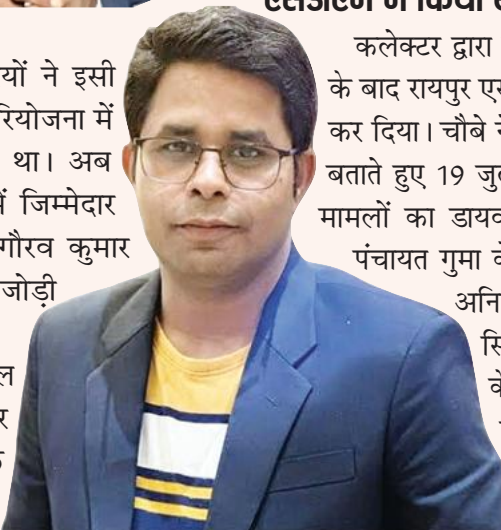
रेल मंत्रालय के पत्र के बाद रायपुर कलेक्टर ने 16 जून 2026 को जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर खास, तिल्दा, आरंग और अभनपुर को पत्र जारी कर करीब 15 गाँवों के जमीनों पर प्रतिबन्ध लगाया। जिसमें रायपुर तहसील के ग्राम पंचायत हथबंद, तेंदुआ-1, गुमा, कारा, कुम्हारी, चिखली, मुरेठी, परसतराई कुरा और तिल्दा तहसील के सिलपट्टी, भुरसुडा, तिल्दा, नेवरा, सिनोधा, सासाहोली और केसला को छोड़कर खपरिकला शामिल है। नियमानुसार इन गाँवों की जमीनों के खरीदी बिक्री, बटांकन और डायवर्सन पर प्रतिबंधित किया गया है।

एसडीएम ने किया खेल..

कलेक्टर द्वारा प्रतिबंध संबंधी पत्र जारी होने के बाद रायपुर एसडीएम नंदकुमार चौबे ने खेल कर दिया। चौबे ने कलेक्टर के आदेश को धता बताते हुए 19 जुलाई 2026 को 25 से अधिक मामलों का डायवर्सन कर दिया। जिसमें ग्राम

पंचायत गुमा के अनिल तिवारी, महेंद्र सिंह, अनिल तिवारी, कुम्हारी के सुरेंद्र सिंह और ऋतिक अग्रवाल, कुरा के सबीहुद्दीन, तेंदुआ के रामसुमिरन वर्मा, रश्मि अग्रवाल, संजय झुनझुनवाला सहित दो दर्जन लोगों का आवासीय और औद्योगिक

डायवर्सन कर दिया। जिन लोगों का डायवर्सन किया गया उनमें अधिकांश व्यापारी और कारोबारी हैं, सभी ने शासन के खजाने में करीब 50 लाख से अधिक डायवर्सन शुल्क भी जमा किया है। एसडीएम कार्यालय में डायवर्सन के हजारों मामले पेंडिंग हैं, पर 19 जुलाई



2026 को एक साथ 25 से अधिक मामलों का डायवर्सन हुआ और सभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से दायरे में है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस खेल में कलेक्टर गौरव सिंह और एसडीएम नंदकुमार चौबे ने रसुखदारों के साथ मिलकर बड़ा खेल किया है।

हंगामा मचा तो सभी डायवर्सन निरस्त-

कलेक्टर ने 30 जुलाई 2026 दोबारा संशोधित आदेश जारी कर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना अंतर्गत आने वाले गाँवों के जमीनों के बिक्री, बटांकन, और डायवर्सन पर बैन लगाने की सूचना दी। तब तक एसडीएम अपनों को उपकृत कर चुके थे। मीडिया में खबरे आई तो हंगामा मच गया। आनन फानन में एसडीएम ने सभी प्रकरणों को 10 अगस्त 2026 को त्रुटिपूर्ण बताकर निरस्त कर दिया। दरअसल एसडीएम को यह अंदाजा नहीं था कि वे फंस जायेंगे। डायवर्सन के लिए आवेदकों द्वारा जमा किये गए डायवर्सन शुल्क करीब 50 लाख रुपये शासन के खाते में जमा है, जिसे वापस लेने उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे।

लीपापोती करने राजस्व निरीक्षक को फंसाया-

डायवर्सन प्रतिबंधित होने के बाद भी एसडीएम ने स्वयं को बचाने भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सभी प्रकरणों का पुनर्विलोकन करने अपीलीय अधिकारी से अनुमति मांगा और सभी मामलों का दोबारा सुनवाई करते हुए आवेदकों पक्ष रखने/तर्क करने का अवसर दिया। यह संयोग है कि 25 से अधिक प्रकरणों में किसी भी आवेदक ने अपना पक्ष नहीं रखा और सभी मामलों को त्रुटिपूर्ण बताते हुए डायवर्सन निरस्त कर दिया। एसडीएम ने पूरे मामले के लिए संबंधित गाँवों के राजस्व निरीक्षक सामवेद शुक्ला को जिम्मेदार बताया कि आरआई द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन भेजे जाने से डायवर्सन हुआ। एसडीएम ने आरआई को कारण बताओ नोटिस जारी करने आदेशित भी किया।

राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार डायवर्सन के खेल में सीधे तौर पर कलेक्टर, एसडीएम और आरआई शामिल है। कलेक्टर के जानकारी बिना एसडीएम आनन फानन में एक दिन में 25 से अधिक डायवर्सन आदेश एक दिन में नहीं कर सकते हैं, मामला बिगड़ने पर लीपापोती करते हुए राजस्व निरीक्षक को बलि का बकरा बनाया गया।

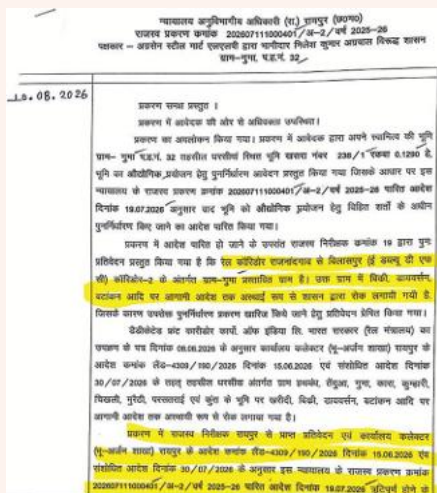
जिम्मेदारी तय नहीं -

इस प्रकरण में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ा खेल किया। राजस्व अधिकारियों के अनुसार लापरवाही बरतने के महीने भर बाद भी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही नहीं की गई है। एसडीएम स्वयं को बचाने राजस्व निरीक्षक सामवेद शुक्ला को जिम्मेदार ठहराया पर न तो उसे निलंबित किया गया ना ही अन्य कोई कार्यवाही।

कलेक्टर और एसडीएम 31 महीने से रायपुर में-

कलेक्टर गौरव सिंह और एसडीएम नंदकुमार चौबे दोनों ही जनवरी 2024 से राजधानी में पदस्थ हैं। आम तौर पर राज्य शासन किसी भी कलेक्टर और एसडीएम को इतना लंबा समय जिलों में नहीं देती पर दोनों के तार शायद अच्छे से जुड़ा है,

शायद इसी के चलते दोनों को नहीं हटाया जा रहा। रायपुर जिले में बीते 31 महीने में जमीनों के डायवर्सन, मठ मंदिर के जमीनों के बंदरबांट हुआ है, अगर इसकी जाँच हो तो एसडीएम जिला प्रशासन के अधिकारियों को कानूनी सहारा पड़ सकता है। राजधानी में मठ मंदिरों की जमीने धड़ल्ले से बिक रही, जबकि उसके लिए कलेक्टर व पंजीयक सार्वजनिक न्यास की अनुमति आवश्यक होती है। ऐसे में उन सभी मामलों की जाँच होना जरूरी है। एसडीएम और कलेक्टर द्वारा किये गए कारनामों को अगले अंको में विस्तार से बताएँगे।



छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल

जीपी सिंह को पुलिस अकादमी की कमान, आनंद छाबड़ा को तकनीकी सेवाओं की जिम्मेदारी



स्वतंत्र बोल डेस्क

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 31 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। इस बदलाव में लंबे समय से चर्चा में रहे जीपी सिंह और डॉ. आनंद छाबड़ा को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। जीपी सिंह को राज्य पुलिस अकादमी का महानिदेशक (DG) बनाया गया है। वहीं 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. आनंद छाबड़ा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG), तकनीकी सेवाएं, डायल-112 एवं दूरसंचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीपी सिंह की नई जिम्मेदारी को पुलिस महकमे में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, राज्य पुलिस अकादमी की जिम्मेदारी के साथ प्रशिक्षण व्यवस्था और पुलिस अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने से जुड़े काम भी उनके कार्यक्षेत्र में

रहेंगे। उनकी नई पदस्थापना ऐसे समय हुई है, जब राज्य पुलिस में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर व्यापक बदलाव किया गया है। सरकार के आदेश में डीजी से लेकर एडीजी, आईजी, डीआईजी और एआईजी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

आनंद छाबड़ा को तकनीकी सेवाओं का जिम्मा

साल 2001 बैच के आईपीएस डॉ. आनंद छाबड़ा को तकनीकी सेवाओं के साथ डायल-112 और दूरसंचार की जिम्मेदारी दी गई है, यानी पुलिस की तकनीकी व्यवस्था, आपातकालीन सहायता सेवा और संचार तंत्र उनके कार्यक्षेत्र में रहेगा। आनंद छाबड़ा को जनवरी 2026 में आईजी से एडीजी पद पर पदोन्नति मिली थी।

हाउसिंग बोर्ड से हटे पवनदेव -

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक प्रदेश में कुल 31 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। विगत छह सालों से पुलिस हाउसिंग में जमे पवन देव को नगर सेना, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने उन्हें हाउसिंग

कारपोरेशन में पदस्थ कर शायद भूल गई थी, लंबे इंतजार के बाद उन्हें पोस्टिंग मिली है। अपने बेहतर कामों के लिए चर्चित दीपांशु विजय काबरा को वर्तमान कार्य के साथ एडीजी रेल एवं यातायात की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।



प्रशासनिक फेरबदल

6 जिलों के कलेक्टर बदले : तोपनो, रणबीर शर्मा, कुंदन कुमार, तुलिका प्रजापति को मिला जिला



और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को नए कलेक्टर मिले।

इन्हे बनाया कलेक्टर-

रणबीर शर्मा को गरियाबंद कलेक्टर, कुंदन कुमार को कांकेर कलेक्टर, तुलिका प्रजापति को कबीरधाम कलेक्टर, अमृत विकास तोपनो को मुंगेली कलेक्टर, जयश्री जैन को सक्ती कलेक्टर, तनुजा सलाम को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का कलेक्टर बनाया गया। कांकेर में कलेक्टर

स्वतंत्र बोल डेस्क

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया, राज्य सरकार ने 22 IAS अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाएं कीं। इस बदलाव में छह जिलों के कलेक्टर भी बदले गए, जबकि मंत्रालय और विभिन्न विभागों में कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। प्रशासनिक फेरबदल में कांकेर, कवर्धा, मुंगेली, गरियाबंद, सक्ती

रहे नीलेश क्षीरसागर को लेकर अनेक तरह की शिकायतें थी जिसके बाद उन्हें मंत्रालय बुलाया गया, तो सक्ती में टॉयलेट साफ करवाने को लेकर विवादों में आये अमृत विकास तोपनो को वह से हटाकर मुंगेली भेजा गया है। रणबीर शर्मा बेमेतरा में कमाल करने के बाद मंत्रालय बुलाया गया था, जो फिर से कलेक्टरी पाने से सफल रहे, उन्हें गरियाबंद का कलेक्टर बनाया गया है।



मंत्रालय में बदली जिम्मेदारियां-

प्रशासनिक फेरबदल से सिर्फ कलेक्टर प्रभावित नहीं हुए, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग और प्रभार भी बदले गए। सोनमणि बोरा को नगरीय



कलेक्टर गोपाल वर्मा को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा रोमा श्रीवास्तव को जिला पंचायत सरगुजा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आकांक्षा शिक्षा खलखो को वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग में उपसचिव के साथ खेल एवं युवा कल्याण विभाग का

प्रशासन एवं विकास विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। लम्बे समय से अच्छे विभाग की बाँट जोह रहे भुवनेश यादव को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला। वहीं नीलेश क्षीरसागर को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक की जिम्मेदारी दी गई। रिमिजियस एक्का नगरीय प्रशासन विभाग में बतौर संचालक थे, उन्हें वहा से हटाकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में विशेष सचिव बनाते हुए जल जीवन मिशन के मिशन संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। एक्का के व्यवहार को लेकर शिकायतें थी और जगदीश सोनकर को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिली।

खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर्स को बुलाया-

जिले में खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर्स को मंत्रालय बुलाया गया। गरियाबंद के तत्कालीन कलेक्टर भगवान सिंह उइके को सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया, वे कुछ महीने बाद रिटायर होंगे। वहीं कवर्धा के तत्कालीन

अतिरिक्त प्रभार और लीना कोसम को नगर पालिक निगम दुर्ग का आयुक्त बनाया गया। प्रदेश के 33 जिलों में 12 जिलों महिला कलेक्टर हैं।

रायपुर दुर्ग बिलासपुर के कलेक्टरों को ढाई साल होने के बाद भी सरकार ने नहीं बदला है। रायपुर में गौरव सिंह, दुर्ग में अभिजीत सिंह, बिलासपुर में संजय अग्रवाल पदस्थ हैं।

पर्यटन मंडल में भी बदला नेतृत्व

फेरबदल में पर्यटन विभाग भी प्रभावित हुआ है। पिछली सरकार ने महत्वपूर्ण पदों में रहे IAS सौमिल रंजन चौबे को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रबंध संचालक बनाया गया। वहीं IFS विवेक आचार्य जो बीते चार सालों से पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक पद पर जमे थे, उन्हें हटाकर उनके मूल विभाग वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वापस भेजा गया।



सब्सो मन के एक खिवैर्या, विष्णु भैया

■ जहां सपनों को मिल रहा अवसर, वहां आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़ ■ गांव-गांव उन्मीद, हर हाथ में अवसर



स्वतंत्र बोल डेस्क

छत्तीसगढ़ की तरक्की की कहानी अब केवल बड़े शहरों और उद्योगों तक सीमित नहीं है। गांव की खेतिहर महिला हो या अपने सपनों को आकार देने वाला युवा, सरकार की योजनाओं ने दोनों के हाथों को अवसर और आत्मनिर्भरता की ताकत दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं, किसानों और युवाओं को केंद्र में रखकर ऐसी पहल की हैं, जिनका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। खेती-किसानी से लेकर स्वरोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और रोजगार तक नई संभावनाओं के रास्ते खुल रहे हैं।

धान छोड़ गेंदा की खेती, आनंद राम ने कमाए 3.96 लाख



रायगढ़ के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम कोड़केल निवासी किसान आनंद राम सिदार ने पारंपरिक धान की खेती छोड़कर गेंदा फूल की खेती अपनाई और आय में बड़ा बदलाव किया। उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में

उन्होंने 0.400 हेक्टेयर सिंचित जमीन पर गेंदा लगाया। इससे करीब 44 क्विंटल फूल का उत्पादन हुआ और बिक्री से 3.96 लाख रुपये मिले। खेती में करीब 55

हजार रुपये खर्च हुए, जिसके बाद उन्हें 3.41 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। पहले इसी जमीन से धान बेचकर करीब 22 हजार रुपये ही लाभ होता था। आनंद राम की सफलता से गांव के अन्य किसान भी उद्यानिकी फसलों के प्रति आकर्षित हुए हैं।

किसान किताब और केसीसी से सोहन की खेती हुई आसान



जशपुर के ग्राम बरगांव डूमरटोली निवासी किसान सोहन सिंह के लिए किसान किताब और किसान क्रेडिट कार्ड खेती में मददगार साबित हुए हैं। केसीसी की सुविधा मिलने से अब उन्हें खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री की व्यवस्था करने में आसानी हो रही है। इससे खेती के जरूरी काम समय पर पूरे करने में भी मदद मिल रही है। सोहन सिंह ने कहा कि किसान किताब और केसीसी किसानों के लिए उपयोगी सुविधा है, जिससे कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना आसान हुआ है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे खेती-किसानी को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

महतारी वंदन से कैलासपति को मिला आर्थिक सहाय

सरगुजा के ग्राम पंचायत थोर की कैलासपति महतारी वंदन योजना से लाभान्वित होकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। योजना के तहत उनके बैंक खाते में हर माह एक हजार रुपये पहुंचते हैं। सालभर में मिलने वाली 12 हजार रुपये की राशि से वे बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरी चीजों पर खर्च करती हैं। कैलासपति

बताती हैं कि सीमित संसाधनों के बीच परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करना कई बार मुश्किल होता था, लेकिन नियमित आर्थिक सहायता से काफी राहत मिली है। सीधे बैंक खाते में राशि मिलने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया।

सीमेंट से हुनर गढ़ रही रुकमणी, हर माह 45 हजार तक आमदनी



रायगढ़ के तमनार विकासखंड के ग्राम देवगढ़ की रुकमणी कुंवर ने अपने हुनर को रोजगार में बदलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। बिहान योजना के तहत स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने ऋण लेकर सीमेंट से मंदिर और सजावटी सामान बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत छोटे स्तर से हुई, लेकिन मेहनत और लगातार प्रयास से काम बढ़ता गया। तैयार सामान की स्थानीय स्तर पर बिक्री से उन्हें हर महीने करीब 45 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। रुकमणी अब परिवार की जरूरतें पूरी करने में आर्थिक योगदान दे रही हैं। उनकी सफलता गांव की दूसरी महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

27 गायों से रोज 60 लीटर दूध, गौपालन बना कमाई का जरिया

जशपुर के नगर पंचायत बगीचा के किसान मधुसुदन भगत ने गौपालन को नियमित आय का मजबूत साधन

बनाया है। वर्ष 2005 से गौपालन कर रहे मधुसुदन के पास वर्तमान में 27 गायें हैं, जिनसे रोजाना 60 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। दूध की स्थानीय बाजार में ही पूरी खपत हो



जाती है। वे पशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखते हैं। गौपालन से मिलने वाले गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर खेतों में उपयोग करते हैं। मधुसुदन का कहना है कि नियमित देखभाल, पौष्टिक आहार और सही प्रबंधन से गौपालन किसानों के लिए स्थायी और बेहतर आय का जरिया बन सकता है।

हथियार छोड़े, हुनर अपनाया; नौकरी के साथ खेती संवारेगे रानू राम

बस्तर के माओवादी संगठन से जुड़े ग्राम ठोटी मड़ानार निवासी रानू राम नेताम ने आत्मसमर्पण के बाद हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन की ओर कदम बढ़ाया है। पुनर्वास नीति के तहत उन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज से ड्राइविंग का प्रशिक्षण लिया और बाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हासिल की। अब वे परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ अपने भविष्य को बेहतर बनाने में जुटे हैं। शासन की योजना से उनके घर के ट्यूबवेल में सोलर पंप भी लगाया गया है, जिससे खेती के लिए सिंचाई की सुविधा मिली है। रानू राम अब नौकरी के साथ खेती को भी आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके जीवन में आए बदलाव ने नई उम्मीद जगाई है।



ऐतिहासिक दूधाधारी मठ

दूध से जुड़ी भक्ति की कहानी..



स्वतंत्र बोल डेस्क

राजधानी रायपुर के मठपारा में स्थित दूधाधारी मठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की धार्मिक आस्था, प्राचीन स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का ऐसा संगम है, जहां पहुंचकर इतिहास और भक्ति दोनों का अनुभव एक साथ होता है। भगवान श्रीराम को समर्पित यह प्राचीन मंदिर रायपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हैं। मंदिर की पहचान सबसे अधिक उसकी रामभक्ति और प्राचीन शिल्पकला से होती है। मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में कालचुरी शासक जैत सिंह से जोड़ा जाता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान श्रीराम से संबंधित सुंदर मूर्तियां और कलात्मक नक्काशी दिखाई देती है। यही स्थापत्य इसे सामान्य मंदिरों से अलग एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल बनाता है।

आखिर क्यों पड़ा नाम 'दूधाधारी'?

इस मंदिर के नाम के पीछे भक्ति और त्याग से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। स्वामी बलभद्र दास भगवान हनुमान के परम भक्त थे और वे अपने जीवन में केवल दूध का सेवन करते थे। इसी कारण उन्हें 'दूध-आहारी'

कहा जाने लगा और कालांतर में इस स्थान की पहचान दूधाधारी मठ के रूप में हो गई।

मान्यता के अनुसार एक गाय भगवान को अर्पित दूध से मूर्ति का अभिषेक करती थी और उसी दूध को स्वामी बलभद्र दास प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। इसी आस्था-कथा ने इस स्थान की धार्मिक पहचान को और विशिष्ट बना दिया।

रामभक्ति की अनूठी विरासत

दूधाधारी मंदिर भगवान श्रीराम को समर्पित वैष्णव परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां रामायण से संबंधित प्राचीन मूर्तिकला और कलाकृतियां इसकी विशेष पहचान हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर रामकथा से जुड़े दृश्य और मूर्तियां इसकी स्थापत्य सुंदरता को अलग आयाम देते हैं। यही वजह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहता, बल्कि वह रामकथा, शिल्प और आध्यात्मिक परंपरा को करीब से देखने का अवसर भी बन जाता है।

मठ और मंदिर, दोनों का संगम

दूधाधारी को केवल मंदिर के रूप में देखना इसके



व्यापक स्वरूप को सीमित कर देता है। भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल के अनुसार यह परिसर एक मठ के रूप में भी धार्मिक साधना, भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ा रहा है। परिसर की संरचना में मंदिरों के साथ साधु-संतों और श्रद्धालुओं से जुड़ी धार्मिक परंपराओं की झलक मिलती है।

आस्था के साथ शिक्षा और समाजसेवा की परंपरा

दूधाधारी मठ की पहचान केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रही है। संस्कृत विद्यालय और दूधाधारी वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना सहित शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का विवरण दिया गया है।

रामनगरी की अनुभूति देता है यह प्राचीन परिसर

रायपुर में जब रामभक्ति की बात होती है तो दूधाधारी मठ का नाम विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है। मंदिर में सुबह और शाम श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है। मंदिर के दर्शन के समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक बताए गए हैं।

रायपुर की पहचान में दर्ज एक आध्यात्मिक विरासत

आज जब रायपुर आधुनिक महानगर के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, तब शहर

के बीचोंबीच मौजूद दूधाधारी मठ उसकी ऐतिहासिक स्मृति को जीवित रखता है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई रामकथा, संत परंपरा से जुड़ी मान्यताएं और सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं इसे केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि रायपुर की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं।

दूधाधारी मठ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां कथा भी है, इतिहास भी, भक्ति भी है और कला भी.. दूध पर जीवन बिताने वाले संत की लोकमान्यता से लेकर भगवान श्रीराम की आराधना और प्राचीन शिल्पकला तक यह परिसर रायपुर की उस विरासत की कहानी कहता है, जिसे समय बदलने के बावजूद श्रद्धा ने आज तक संभालकर रखा है।



नेपाल में बाढ़ का रौद्र रूप, हजारों की मौत.. भीषण तबाही



स्वतंत्र बोल डेस्क

नेपाल में बुधवार 26 अगस्त 2026 की सुबह करीब 9 बजे उत्तरी जिला रसुवा में भोटेकोशी नदी अचानक उफान पर आ गई। चीन के तिब्बत क्षेत्र से आने वाले इस अचानक सैलाब ने सीमा के पास बसे तिमुरे और रयाफ्रुबेसी इलाकों को तहस-नहस कर दिया। गांव के गांव बह गए, बाजार तबाह हो गए, पुल टूट गए और सड़कें कट गईं।

नेपाल और तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने हिमालयी इलाके में भारी तबाही मचा दी है। 26 अगस्त को शुरू हुई इस त्रासदी के बाद कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए, सड़क और संपर्क व्यवस्था बाधित हुई और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस आपदा का असर भारत तक पहुंचा है और बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के अब भी लापता होने की जानकारी सामने आई है।

हजारों लोगों पर टूटा संकट

आपदा के बाद नेपाल के कई हिस्सों में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। तेज बहाव के साथ आया मलबा अपने रास्ते में आने वाली सड़क, पुल और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचाता चला गया। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में राहत दलों को पहुंचने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समय बीतने के साथ राहत अभियान का फोकस अब प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ लापता लोगों की तलाश और मृतकों की पहचान पर है। अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी आंकड़ों में अंतर है, क्योंकि कई इलाकों में सत्यापन की प्रक्रिया अभी जारी है।

275 भारतीय अब भी लापता

भारत के लिए इस त्रासदी की सबसे बड़ी चिंता वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को लेकर है। 4 सितंबर को सामने आए विदेश मंत्रालय के अपडेट के अनुसार 275 भारतीय नागरिकों के अब भी लापता होने की जानकारी है। वहीं 166 भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका

है। तिब्बत के रास्ते नेपाल पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की भी बड़ी संख्या है। जानकारी के मुताबिक 1,907 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं और तिब्बत में अब कोई भारतीय यात्री फंसा नहीं है।

भारत सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य में सहायता के लिए विशेषज्ञ दल भी भेजे गए हैं। राहत सामग्री भी नेपाल पहुंचाई गई है।

छत्तीसगढ़ के दो डॉक्टरों को लेकर चिंता

नेपाल की इस त्रासदी ने छत्तीसगढ़ के कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के कुछ लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे।

अंबिकापुर की डॉ. मीना गुप्ता और बिलासपुर की डॉ. प्रियंका चौधरी को लेकर परिवार और प्रशासन लगातार जानकारी जुटाने में लगे हैं। आपदा के बाद दोनों से संपर्क नहीं हुआ।

अंबिकापुर की डॉ. मीना गुप्ता कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थीं। जिस समय आपदा आई, उस दौरान उनका समूह नेपाल और तिब्बत सीमा क्षेत्र के इमिग्रेशन सेंटर के आसपास था। बाढ़ और भूस्खलन के बाद उनसे संपर्क नहीं हो सका। परिवार लगातार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा है। घटना के कई दिन बाद भी उनका कोई स्पष्ट सुराग सामने नहीं आया था।

डॉ. प्रियंका चौधरी से भी संपर्क टूटा



बिलासपुर की डॉ. प्रियंका चौधरी भी इस आपदा के बाद लापता बताई गई हैं। वह फिनलैंड में कार्यरत थीं और यात्रा के लिए नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में गई थीं। परिवार के अनुसार आपदा से पहले उनसे बातचीत हुई थी। इसके बाद संपर्क टूट गया। परिवार और प्रशासन उनकी स्थिति की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।

मंजू राय चौधरी को लेकर मिली राहत की खबर

बिलासपुर की 65 वर्षीय मंजू राय चौधरी का नाम भी शुरुआती तौर पर संपर्क से बाहर लोगों में सामने आया था। बाद में उनके सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई।

भारत ने भेजा राहत सामग्री

भारत ने नेपाल में राहत और बचाव अभियान में सहयोग बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है। इसके अलावा टनल रेस्क्यू, फॉरेंसिक और मेडिकल विशेषज्ञों सहित 54 सदस्यीय विशेषज्ञ दल को भी सहायता के लिए भेजा गया है। लापता भारतीयों की जानकारी जुटाने के लिए भारतीय और नेपाली एजेंसियों के बीच समन्वय किया जा रहा है। परिवारों से उपलब्ध पहचान संबंधी दस्तावेज और दूसरी जानकारी भी जुटाई जा रही है।

मलबे के बीच तलाश सबसे बड़ी चुनौती

आपदा के कई दिन बाद भी खोज और बचाव अभियान आसान नहीं हुआ है। पहाड़ी इलाकों में जमा मलबा, क्षतिग्रस्त रास्ते और मौसम की स्थिति बचाव दलों के सामने बड़ी चुनौती हैं।

कई स्थानों पर लापता लोगों की तलाश के लिए विशेष बचाव दलों के साथ आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बरामद शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी तबाही



हिमालयी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और भारी मलबे ने इस आपदा को बेहद विनाशकारी बना दिया। शुरुआती रिपोर्टों में ग्लेशियर और बर्फाले क्षेत्रों से अचानक पानी आने तथा उससे पैदा हुए तेज बहाव और मलबे की आशंका जताई गई है।



1340 से ज्यादा मौतें, 5000 लापता...

नेपाल में उस तबाही ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। 26 अगस्त को आई फलैश फ्लड में अब तक 1,340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। सरकार ने 7 सितंबर को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया है। सरकारी दफ्तरों से लेकर विदेशों में मौजूद नेपाली दूतावासों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। यह दिन बाढ़ के 13वें दिन रखा गया है। हिंदू परंपरा में किसी की मौत के बाद 13वां दिन शोक से जुड़ा अहम समय माना जाता है। इसी वजह से नेपाल ने इस दिन अपने लोगों को याद करने का फैसला किया। 26 अगस्त को चीन की सीमा से लगे रसुवा इलाके में ऊंचे हिमालय पर बर्फ और चट्टानों के खिसकने के बाद अचानक फलैश फ्लड आई। इसका असर रसुवा के साथ नुवाकोट, धादिंग समेत कई इलाकों में पड़ा। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इसके चलते, कई घर बह गए, सड़कें टूट गईं, पुल क्षतिग्रस्त हुए। हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, सरकारी इमारतें समेत जरूरी बुनियादी ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस आपदा से कम से कम 32 हजार परिवार विस्थापित हुए हैं। करीब 7,500 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता उन 5,000 लोगों को लेकर है, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। इनमें 589 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। राहत की टीमों का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कई जगहों के मलबे में तलाश चल रही है।

हाई कोर्ट का निर्णय

अदालत में पीड़ित और गवाहों को मिलेगा सम्मान..

स्वतंत्र बोल डेस्क

छत्तीसगढ़ में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब अदालतों के फैसलों से लेकर पुलिस की एफआईआर और चार्जशीट तक में ऐसी भाषा के इस्तेमाल से बचना होगा, जो महिलाओं या किसी पीड़ित के प्रति लैंगिक भेदभाव अथवा सामाजिक रूढ़ियों को बढ़ावा देती हो। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश की अदालतों और संबंधित विभागों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेश की प्रति प्रदेश के



सभी 24 जिला एवं सत्र न्यायालयों के साथ स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी, राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्य सचिव, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी गई है। संबंधित संस्थाओं को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदलाव

यह पूरा बदलाव सुप्रीम कोर्ट की उस पहल के बाद सामने आया है, जिसमें न्यायिक आदेशों में महिलाओं के प्रति इस्तेमाल होने वाली असंवेदनशील और आपत्तिजनक भाषा पर चिंता जताई गई थी। एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले में की गई टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद

रिटायर्ड जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने न्यायिक लेखन में लैंगिक संवेदनशीलता और करुणा से जुड़े विषय पर रिपोर्ट तैयार की।

सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर तैयार दिशा-निर्देशों को देशभर की अदालतों में लागू करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में अब छत्तीसगढ़ में भी न्यायिक आदेशों, पुलिस कार्रवाई और पीड़ितों के साथ व्यवहार को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है।

एफआईआर और चार्जशीट की भाषा भी बदलेगी..

नई व्यवस्था का एक अहम हिस्सा पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। एफआईआर दर्ज करते समय या चार्जशीट तैयार करते हुए महिलाओं के पहनावे, व्यवहार, चाल-चलन या चरित्र से संबंधित ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो पूर्वाग्रह पैदा करती हो या पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो यानी किसी अपराध की जांच और कानूनी कार्रवाई में महिला के व्यक्तिगत जीवन या चरित्र को केंद्र में रखने के बजाय घटना, उपलब्ध साक्ष्य और कानून के प्रावधानों पर ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत दर्ज कराने वाली महिला को पुलिस प्रक्रिया के दौरान ही किसी तरह के सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना न करना पड़े।

पुराने शब्दों की जगह संवेदनशील शब्दावली

दिशा-निर्देशों में न्यायिक लेखन और कानूनी दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली को भी संवेदनशील बनाने पर जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले कई पुराने और रूढ़िवादी शब्दों की जगह तटस्थ तथा सम्मानजनक शब्दों के इस्तेमाल की बात कही गई है।

उदाहरण के तौर पर 'लाचार महिला' या 'बेबस औरत' जैसे शब्दों के स्थान पर 'महिला', 'सर्वाइवर' या

‘विक्टिम’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह ‘हवस’ जैसे शब्दों की जगह यौन हमले या यौन हिंसा जैसी कानूनी एवं स्पष्ट शब्दावली को प्राथमिकता दी जाएगी।

किसी महिला के चरित्र पर टिप्पणी करने के बजाय मामले से जुड़े तथ्य और साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। ‘रखैल’ या ‘कीप’ जैसे शब्दों की जगह ‘पार्टनर’ या ‘महिला मित्र’ जैसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह ‘वेश्या’ या ‘कॉलगल’ के स्थान पर ‘सेक्स वर्कर’ जैसे शब्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी सम्मानजनक और स्वीकार्य शब्दावली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत में पीड़ित और गवाह को मिलेगा सम्मान

नई व्यवस्था केवल भाषा तक सीमित नहीं है। अदालत में आने वाले पीड़ितों और गवाहों के साथ व्यवहार को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्हें लंबे समय तक खड़े रहने या अनावश्यक इंतजार करने की स्थिति से बचाने पर जोर दिया गया है। अदालत परिसर में उनके बैठने के लिए कुर्सी, पानी और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

इसका उद्देश्य न्यायालय आने वाले पीड़ित और गवाह को यह महसूस कराना है कि न्यायिक प्रक्रिया उनके लिए भय या असहजता का कारण नहीं, बल्कि सहायता और न्याय प्राप्त करने का माध्यम है।

यौन अपराध और पॉक्सो मामलों में गोपनीयता

यौन अपराधों और पॉक्सो से जुड़े मामलों में पीड़िता की निजता और पहचान की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। ऐसे मामलों की सुनवाई जरूरत के अनुसार बंद कमरे में यानी इन-कैमरा की जाएगी। पीड़िता की पहचान सार्वजनिक न हो, इसके लिए आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

इसका मकसद पीड़िता को सामाजिक दबाव, बदनामी और मानसिक परेशानी से बचाते हुए उसे सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।

न्यायिक अधिकारियों और पुलिस की होगी ट्रेनिंग

इन बदलावों को केवल आदेश तक सीमित न रखते

हुए न्यायिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिलासपुर स्थित छतीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी को न्यायिक अधिकारियों, सरकारी वकीलों और पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रशिक्षण के दौरान न्यायिक आदेशों और पुलिस दस्तावेजों में लैंगिक पूर्वाग्रह से बचने, पीड़ितों की गरिमा बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया को अधिक पीड़ित-केंद्रित बनाने पर जोर दिया जाएगा।

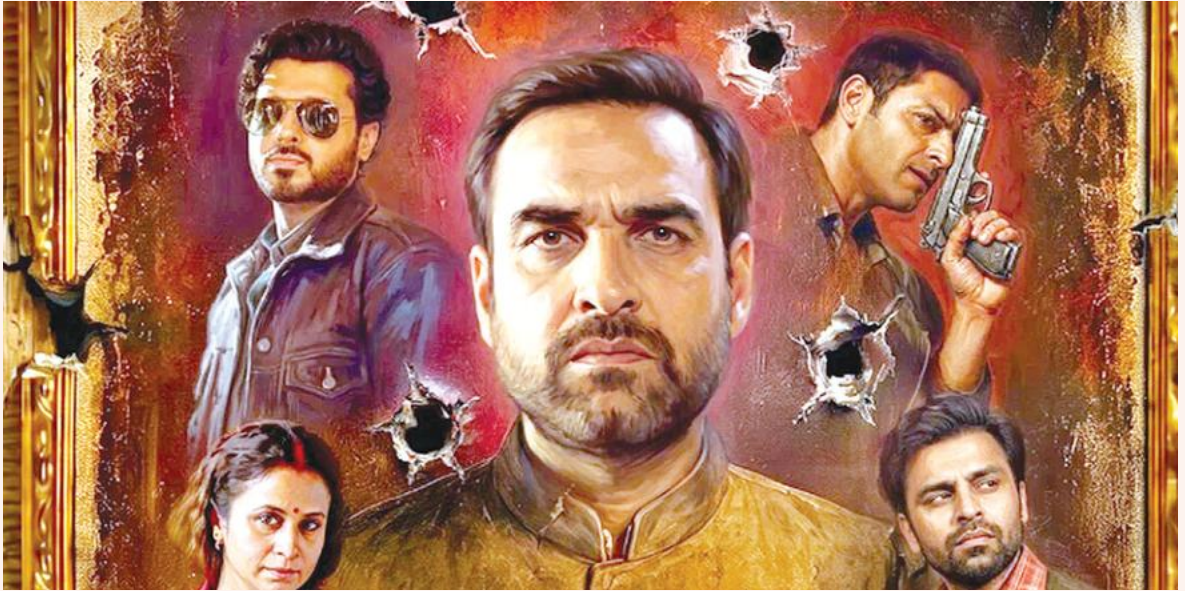
पीड़िताओं को जल्द मिलेगी अंतरिम राहत

यौन उत्पीड़न और एसिड अटैक जैसी घटनाओं की पीड़िताओं को आर्थिक एवं पुनर्वास संबंधी सहायता दिलाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से नालसा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम-2018 के तहत पात्र पीड़िताओं को त्वरित अंतरिम राहत राशि और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे कानूनी लड़ाई के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रही पीड़िताओं को शुरुआती स्तर पर सहायता मिल सकेगी।

न्याय व्यवस्था में भाषा बदलने की पहल

दरअसल, किसी न्यायिक आदेश या पुलिस दस्तावेज में इस्तेमाल होने वाले शब्द केवल औपचारिक भाषा का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उनका असर पीड़ित की गरिमा और समाज की सोच पर भी पड़ सकता है। महिलाओं के कपड़ों, चरित्र या निजी जीवन को अपराध की परिस्थितियों से जोड़कर देखने वाली भाषा कई बार पीड़िता के लिए अतिरिक्त मानसिक दबाव पैदा करती है। नई व्यवस्था में इसी सोच को बदलने की कोशिश की गई है। अब न्यायिक प्रक्रिया में व्यक्ति के चरित्र या सामाजिक धारणाओं के बजाय घटना के तथ्य, उपलब्ध साक्ष्य और कानून को आधार बनाया जाएगा। इससे अदालतों और पुलिस थानों में पीड़ितों के लिए अधिक सम्मानजनक, निष्पक्ष और भरोसेमंद वातावरण तैयार करने की उम्मीद है।



‘मिर्जापुर द मूवी’ बनी 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर

स्वतंत्र बोल डेस्क

पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। ‘हनुमान अंश’ की आंधी के बीच फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स भी बना रही है। इसकी रिलीज को 10 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने अपने दूसरे सप्ते को भी शानदार बिजनेस किया है, जिसके बाद इसने 2026 की टॉप 5 फिल्मों में एंट्री मार ली है।

‘मिर्जापुर द मूवी’ का दसवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘मिर्जापुर द मूवी’ को वर्ड ऑफ माउथ का भरपूर फायदा मिल रहा है। फिल्म 10वें दिन भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। इसे हिट फ्रेंचाइजी का पूरा फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से कालीन भैया और गुड्डू पंडित तक सभी किरदार बड़े पर्दे पर भी छा गए हैं। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 25.75 करोड़ का कारोबार किया था।

- वहीं, फिल्म का पहले हफ्ते का इंडिया नेट कलेक्शन 148.45 करोड़ रहा था।
- अब इसने दूसरे हफ्ते 8वें दिन 9.50 करोड़ तो 9वें दिन दूसरे शनिवार को 13.50 करोड़ का कारोबार किया था।

2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर बनी ‘मिर्जापुर द मूवी’

इसी के साथ ही फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ 2026 की इंडिया की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। इसने धमाल 4 (177.92 करोड़) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इसकी 2026 की टॉप 5 फिल्मों में एंट्री हो चुकी है। देखिए इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 1186.32 करोड़
2. बॉर्डर 2- 362.76 करोड़
3. हनुमान अंश- 214.88 करोड़
4. भूत बंगला- 199.23 करोड़
5. मिर्जापुर द मूवी- 184.95 करोड़
6. धमाल 4- 177.92 करोड़
7. आवारापन 2- 156.05 करोड़
8. टॉक्सिक (हिंदी)- 149.07 करोड़
9. वेलकम टू द जंगल- 137.93 करोड़
10. कॉकटेल 2- 104.53 करोड़

‘मिर्जापुर द मूवी’ ने 5 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

इसके साथ ही फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ इंडिया की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने के साथ ही 2026 की टॉप 5 फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है।

आशा भोसले की जयंती पर रिलीज हुआ 'ऐ मेरी जिंदगी'

स्वतंत्र बोल डेस्क



भारतीय संगीत की दिग्गज गायिका आशा भोसले की जयंती का दिन उनके चाहने वालों के लिए बेहद खास बन गया। इसी अवसर पर उनकी आखिरी फीचर फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए गीत 'ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहाँ' को रिलीज किया गया। यह गीत निर्देशक हरीश व्यास की फिल्म 'ओम का हरि' का हिस्सा है। फिल्म में रघुबीर यादव, सोनी राजदान और अंशुमन झा अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। गीत के साथ फिल्म का म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया गया, जिसने इस आयोजन को भावनात्मक और यादगार बना दिया।

आशा भोसले के आखिरी फीचर फिल्म गीत की खास झलक

'ओम का हरि' के म्यूजिक एल्बम की सबसे बड़ी खासियत आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किया गया यह गीत है। इसे उनकी फीचर फिल्मों के लिए रिकॉर्ड किए गए आखिरी गानों में शामिल किया जा रहा है। गाने का म्यूजिक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में बिताए गए आशा भोसले के कुछ अनमोल पलों को दिखाया गया है। वीडियो के जरिए दर्शकों को यह देखने का मौका मिलेगा कि

आशा भोसले ने फिल्म के इस गीत को किस तरह अपनी आवाज दी थी। उनकी आवाज और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के इन पलों ने गाने को सिर्फ एक म्यूजिकल रिलीज न रहकर एक यादगार दस्तावेज जैसा बना दिया है।

कई पीढ़ियों के संगीत को एक साथ जोड़ता है एल्बम

'ओम का हरि' का म्यूजिक एल्बम फिल्म की कहानी के साथ-साथ भारतीय संगीत की अलग-अलग पीढ़ियों की विरासत को भी जोड़ता है। एल्बम में दिवंगत महान गायक किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार की आवाज में भी गीत शामिल हैं। इसके अलावा परेश पाहुजा ने भी इस फिल्म के लिए अपनी आवाज दी है। फिल्म के मुख्य कलाकार रघुबीर यादव ने भी एल्बम के लिए दो गाने गाए हैं। म्यूजिक लॉन्च के दौरान उन्होंने इन दोनों गीतों की लाइव प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और खास बना दिया। उनकी परफॉर्मेंस को वहां मौजूद दर्शकों ने खूब सराहा।

अंशुमन झा ने बताया इसे खास संयोग

म्यूजिक लॉन्च के मौके पर अंशुमन झा ने आशा भोसले की संगीत यात्रा और फिल्म से उनके जुड़ाव को लेकर अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में प्लेलिस्ट का चलन आम होने से बहुत पहले ही आशा भोसले अपने आप में एक पूरी प्लेलिस्ट जैसी थीं। उनके मुताबिक 'ओम का हरि' के लिए आशा जी का गाना रिकॉर्ड करना फिल्म से जुड़े लोगों के लिए बेहद सम्मान की बात है। अंशुमन ने यह भी कहा कि आशा भोसले की जयंती पर उनके आखिरी फीचर फिल्म गीत का रिलीज होना अपने आप में बेहद खूबसूरत संयोग है।

‘ट्रॉफी चोर’ के नारों से गुंजा दुबई का मैदान

महिला क्रिकेट टीम ने जीता एशिया कप..

स्वतंत्र बोल डेस्क

दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार विमेंस एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम की जीत के बाद पुरस्कार समारोह के दौरान ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने पिछले साल के विवाद की यादें ताजा कर दीं।

फाइनल खत्म होने के बाद एशियन क्रिकेट का 1 उं सिल (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी प्रेजेंटेशन स्टेज पर मौजूद थे। हालांकि, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए मंच पर नहीं आई। नकवी ने श्रीलंका

की कप्तान चमारी अटापट्टु को रनरअप चेक सौंपा और इसके बाद स्टेडियम से निकल गए।

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी जब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, तभी दर्शकों की तरफ से ‘ट्रॉफी चोर-ट्रॉफी चोर’ के नारे सुनाई दिए। यह वही नारा है, जो 2025 के मेन्स एशिया कप फाइनल के बाद हुए ट्रॉफी विवाद के दौरान नकवी

को लेकर चर्चा में आया था।

8वीं बार चैंपियन बना भारत, फाइनल में श्रीलंका को हराया

पिछले साल दुबई में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता था। उस मुकाबले के बाद पुरस्कार समारोह में एक घंटे से ज्यादा की देरी हुई थी। भारतीय

टीम ने नकवी से ट्रॉफी नहीं थी, जिसके बाद एसीसी चेयरमैन ट्रॉफी लेकर फुर् हो गए थे। वो ट्रॉफी अब भी दुबई स्थित एसीसी के मुख्यालय में रखी है। उस ट्रॉफी विवाद के बाद सोशल मीडिया पर ‘ट्रॉफी चोर’ का नारा काफी चर्चित हुआ था और पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई।

महिला एशिया कप के फाइनल में भी ट्रॉफी प्रेजेंटेशन



विवादों में आ गया। भारत ने खिताब जीत लिया, लेकिन टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इंकार किया। BCCI (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) सचिव देवजीत सैकिया ने इस विवाद पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि महिला टीम ने पिछले साल पुरुष टीम के फैसले के प्रति एकजुटता दिखाई है और मौजूदा परिस्थितियों में बीसीसीआई अपना रुख नहीं बदल सकता।

नकवी संग दिखे BCCI के अधिकारी?

मोहसिन नकवी मैच के दौरान बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और देवजीत सैकिया के साथ रॉयल बॉक्स में नजर आए थे. इसके बाद सवाल उठे कि जब ट्रॉफी लेने से इनकार किया गया तो मैच के दौरान अधिकारियों की नकवी से बातचीत क्यों हुई? देवजीत सैकिया ने इसे सामान्य प्रोटोकॉल बताया. उन्होंने कहा कि मैच के दौरान रॉयल बॉक्स में मौजूद लोगों का एक-दूसरे से मिलना और बातचीत करना सामान्य परंपरा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बातचीत का ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के फैसले से कोई संबंध नहीं था।

देवजीत सैकिया ने यह भी बताया कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन की स्थिति को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं बन सकी. हालांकि, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है।



उनके मुताबिक भारत की प्राथमिकता ट्रॉफी किसके हाथों से मिले, यह नहीं थी. सबसे अहम लक्ष्य महिला टीम का एशिया कप जीतना था और टीम ने वो टारगेट हासिल कर लिया।

तीर से दुनिया जीत रहा छत्तीसगढ़ का बेटा



छत्तीसगढ़ के तोमन कुमार ने अंतरराष्ट्रीय पैरा आर्चरी में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया है। तोमन ने अहमदाबाद में हुए हुंडई वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज स्टेज-3 2026 में तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी की भारतीय जोड़ी ने पुरुष कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। फाइनल में भारत ने इराक की अब्बास काधिम और अनवर अल्दावूद की जोड़ी को 152-139 से हराया।

छत्तीसगढ़ से विश्व मंच तक पहुंचने की कहानी-

एक छोटे से गाँव से निकलकर विश्वमंच तक पहुंचना किसी भी आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। तोमन कुमार की कहानी फिल्मी जैसी है, जिसने कठिन परिस्थितियों के बाद भी धैर्य और अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। तोमन बालोद जिले रहवासी है और CRPF में सेवा दे चुके हैं। साल 2022 में एक नक्सली IED विस्फोट में अपना पैर गंवा बैठे थे, इसके बाद उन्होंने जिंदगी को रुकने नहीं दिया और पैरा आर्चरी को अपना नया रास्ता बनाया। CRPF ने भी उन्हें विश्व पैरा आर्चरी चैंपियन बनने पर सम्मानित किया था। आज वही तोमन कुमार विश्व स्तर के पैरा तीरंदाजों में अपनी जगह बना चुके हैं। वर्ल्ड आर्चरी की आधिकारिक प्रोफाइल में भी उन्हें शीर्ष स्तर के कंपाउंड पैरा आर्चर के रूप में दर्ज किया गया है।



तोमन की शानदार जीत

2026 की वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज का अहमदाबाद चरण भारत के लिए खास है, क्योंकि देश पहली बार इस सीरीज की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 5 से 9 सितंबर 2026 तक साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित की गई। भारतीय दल में तोमन कुमार के अलावा पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी, हरविंदर सिंह, राकेश कुमार समेत कई प्रमुख तीरंदाज शामिल हैं। 8 सितंबर को पुरुष कंपाउंड टीम फाइनल में तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने इराक की जोड़ी के खिलाफ शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और अंत में 152-139 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।

सिर्फ मेडल नहीं, बेहतर प्रदर्शन भी

तोमन की इस सफलता को उनके पूरे अंतरराष्ट्रीय सफर से जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर और बड़ी नजर आती है। अप्रैल 2026 में बैंकॉक में आयोजित World Archery Para Series के पहले चरण में तोमन ने पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जोनाथन मिल्ले को 146-142 से हराया था। अहमदाबाद में

उनकी सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यहां केवल व्यक्तिगत खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि भारतीय टीम के अहम सदस्य के रूप में भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। तोमन कुमार की कहानी किसी एक प्रतियोगिता के पदक तक सीमित नहीं है। यह उस जज्बे की कहानी है जिसमें एक खिलाड़ी ने जीवन बदल देने वाली मुश्किल के बाद अपने लिए एक नया लक्ष्य चुना और फिर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच बनाया। तीरंदाजी में लक्ष्य सामने होता है, लेकिन उसे

भेदने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि एकाग्रता, धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। तोमन का सफर इन्हीं तीनों चीजों का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी गौरव की बात है कि प्रदेश का एक खिलाड़ी अब विश्व पैरा आर्चरी के बड़े मंच पर भारत की पदक उम्मीदों का हिस्सा बन चुका है।

तोमन कुमार

- **खेल:** पैरा आर्चरी
- **स्पर्धा:** कंपाउंड
- **राज्य:** छत्तीसगढ़
- **हालिया उपलब्धि:** World Archery Para Series, अहमदाबाद में पुरुष कंपाउंड टीम गोल्ड
- **साथी:** श्याम सुंदर स्वामी
- **फाइनल स्कोर:** भारत 152, इराक 139
- **2026 की बड़ी उपलब्धि:** बैंकॉक चरण में पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्वर्ण
- **अहमदाबाद चरण:** 5 से 9 सितंबर 2026
- **विशेष पहचान:** विश्व चैंपियन तीरंदाज और छत्तीसगढ़ से आने वाले प्रमुख पैरा आर्चर।

- निवेदन -

स्वतंत्र बोल से संबंधित कोई भी झुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। फोन और ई-मेल पर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र से घटित कोई घटना, समाचार, या अन्य कोई गतिविधि जो पत्रिका में प्रकाशन योग्य हो.. तो उससे भी भेज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय हिन्दी मासिक पत्रिका
तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल और न्यूज वेबसाइट को निर्भीक और
जनपक्षीय पत्रकारिता के लिये आर्थिक रूप से सहयोग करें।

बंधन बैंक

बैंक खाता नंबर - 20100031810292
आईएफएससी कोड - BDBL0001958



संपादक स्वतंत्र बोल

डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)

97543-74333, bolswatantra@gmail.com



छत्तीसगढ़ शासन



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ में
उद्योग स्थापना की प्रक्रिया है

बेहद आसान

सिंगल विंडो 2.0

सरल, तेज और पारदर्शी



उद्योग स्थापना से जुड़ी

150+ सेवाएं

और सभी आवश्यक
अप्रूवल



सिर्फ एक क्लिक पर...

अधिक जानकारी
के लिए
क्यूआर कोड
स्कैन करें



सिंगल विंडो 2.0 के फायदे



समयबद्ध
निपटान



पूरी प्रक्रिया
डिजिटल



रियल टाइम
ट्रैकिंग और
अपडेट



एक ही
प्लेटफॉर्म पर
सभी सेवाएं



उद्योगों के लिए
अनेक सरकारी प्रोत्साहन



कम समय
कम प्रयास



सुरक्षित
और विश्वसनीय



सरकार आपके
साथ हर कदम पर

नया छत्तीसगढ़, नए अवसर, नई उड़ान